भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या : 877

दिनांक 17 सितम्बर , 2020 / 26 भाद्रपद, 1942 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

हवाई पट्टियों के विकास हेतु प्रस्ताव

877. **श्री संगम लाल गुप्ता:**

श्री सी.पी. जोशी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देशभर में हवाई पट्टियों के विकास हेतु नए प्रस्तावों पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों ने इस संबंध में सरकार को सूचित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु निर्दिष्ट स्थानों के नाम क्या है; और

(ग) क्या सरकार के पास राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों की तीर्थ पर्यटन क्षमता के उपयोग की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) और (ख): भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय ने अल्पसेवित और असेवित हवाईअड्डों को क्षेत्रीय हवाई संपर्कता की सुविधा प्रदान/ प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अक्तूबर, 2016 में क्षेत्रीय संपर्कता योजना (आरसीएस) – उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) आरंभ की। हवाईपट्टियों/हवाईअड्डों का पुनरुत्थान "माँग पर आधारित" है, जो एयरलाइन प्रचालकों के साथ-साथ विविध रियायतें प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता पर आधारित है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) द्वारा राजस्थान में बीकानेर, जैसलमर, किशनगढ़, कोटा और उतरलाई तथा उत्तर प्रदेश में आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, बरेली, कानपुर, चित्रकूट, अयोध्या, गाजीपुर, झाँसी, मुरादाबाद, कुशीनगर, मुज़रपुर, आज़मगढ़, श्रावस्ती, सहारनपुर और हिंडन हवाईअड्डों का विकास आरसीएस-उड़ान के अंतर्गत किया गया है।

(ग): राजस्थान में किशनगढ़ तथा उत्तर प्रदेश में चित्रकूट, अयोध्या, कुशीनगर और श्रावस्ती हवाईअड्डों का विकास भाविप्रा द्वारा उस क्षेत्र की तीर्थस्थान पर्यटन संभाव्यता का लाभ उठाने के लिए किया गया है।

*****